

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 32/14

1. कैलाश पुत्र किशनलाल जाति नायक निवासी ग्राम पीपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. किशनलाल पुत्र भूसा जाति नायक निवासी ग्राम पिपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नरपत सिंह
2. उम्मेद सिंह
3. गणपत सिंह पुत्रान नन्दलाल सिंह जातियान कोठयारी राजपूत निवासी पिपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. कल्याण पुत्र बालू जाति धोबी निवासी पिपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. नानगा पुत्र पोखर (मृतक)
5/1. राजेन्द्र पुत्र नानगा जाति नायक
5/2. मु० जमबो बेवा नानगा जाति नायब निवासीयान पिपल्या तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

... रेस्पोंडेन्टान

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु०न० 366/11 निर्णय दिनांक 14.5.14)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री रंगलाल गुर्जर
2. रेस्पोंडेंट 1 से 3 की और से श्री सुधीर कुमार जैन

निर्णय

दिनांक 10.2.2020

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु०न० 366/11 निर्णय व डिग्री दिनांक 14.5.14 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पों/वादी 1 ता 3 ने एक दावा बाबत दिलाये जाने कब्जा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183 इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीपल्या की आराजी ख०न० 1110,1111,1115,1116,1117 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.88 है० जो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। पूर्व में इस भूमि का ख०न० 653 था। प्रतिवादीगण 1: व 2 ने वादीगण की आराजी ख०न० 1116 रकबा 0.05 है० पर बाडा व मकान बनाकर एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने ख०न० 1117 रकबा 0.01 है० पर बाडा बनाकर तथा प्रतिवादी न० 4 व 5 ने ख०न० 1117 में 0.01 है० पर बाडा बनाकर जबरन वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कांटो की वाड लगाकर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा सन 1995 में उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा व मकान बनाने का प्रयास करने पर वादीगण के पिता द्वारा तहसीलदार को शिकायत करने पर तहसीलदार प्रतिवादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण हटवा दिया था तथा जमीन खाली करवा दी थी। तत्समय प्रतिवादीगण ने वादीगण के हक में पाँच रूपये का स्टाम्प पेपर पर

यह लिख कर दे दिया कि हमने बाड़ा बगैर हटा लिया है मकान को फोड़कर मलबा हटा लिया है। अब भविष्य में वादीगण की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। दिनांक 10.9.05 को प्रतिवादीगण ने फिर वादीगण को परेशान करना शुरू कर दिया व उक्त भूमि पर दुबारा अतिक्रमण कर बाड़ा व खाम मकान निर्माण कर लिया जिसकी बजह से वादीगण की काश्त की भूमि को जबरन अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिया जिससे वादीगण के खेत का रास्ता बंद हो जाने की आशंका हो गई। प्रतिवादीगण अपने धनबल एवं भुजबल के घमण्ड पर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया है तथा वादीगण की कृषि भूमि को जबरन अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को काफी समझाने का प्रयास किया तो उल्टा प्रतिवादीगण ने वादीगण से काफी गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी गई। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय की शरण लेकर वादीगण की उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करे न कोई निर्माण कार्य कर अतिक्रमण करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो० का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्त/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सवाई सुनी गई।

अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अपीलान्तान जिस स्थान पर काबिज है, उस स्थान पर दो रास्ते बने हुए हैं एक रास्ता महापुरा पंचायत की ओर से आकर ग्राम पिपलाई में जाता है तथा रास्ता शिवाड से ग्राम पिपलाई में आता है। रेस्पो० का ख०न० का रकबा उनके कब्जे के रकबे से बिलकुल अलग है। रेस्पो० ने पूर्व से पश्चिम की तरफ अपीलान्तान के मकान व बाड़े के पीछे डोल लगा रखी है। तथा दोनों स्थान अर्थात् रेस्पो० की जमीन एवं अपीलान्तान के मकान व बाड़े पृथक पृथक बने हुए हैं। बद्दीसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपल्या जो कि ग्राम जटवाडा का रहने वाला है तथा सदैव से ही मकान बनाकर रहता है तथा तहसील में जमादार की हैसियत से सर्विस करता था उस समय उसे अवैध रूप से मिलीभगत करके भूमि अपने नाम नियमन करा ली थी जबकि वह राजकीय सेवा में था एवं उसके पक्ष में इस संबंध आशय का कोई भी आवंटन नियमन स्वतः ही निरस्त योग्य है। रेस्पो/वादी द्वारा मौके पर कभी भी कोई जमीन न तो काश्त की और ना ही भौतिक रूप से उसका कभी कब्जा रहा बल्कि उसने अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए तत्कालीन तहसीलदार से मिलकर भूमि अपने पक्ष में नियमन कराई है। लिहाजा इस प्रकार का कोई भी नियमन आदेश

जिसका आधार पर भूमि वादीगण/रेस्पो० को बची गई है स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि मुतवादिया पर अपीलांट का 45 वर्षों से बाडा व मकान बना हुआ है एवं उनके इस कब्जे के विरुद्ध बंदी हिस अथवा रेस्पो० का खातेदारी इन्द्राज का कोई महत्व नहीं है। धारा 183 आर टी एक्ट के अन्तर्गत दावा दखलयाबी लाने के लिए मियाद निश्चित एवं 40 वर्ष के देरीना कब्जे से अपीलांट से कोई बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसलिए दावा मियाद बाहर है। पुरानी गिरदावरियों में यह जमीन पडत बंजर है जो तथ्य को साबित करती है कि भूमि पर कभी रेस्पो० का कब्जा काशत नहीं रहा है। आवंटी बंदीसिह द्वारा जो आवंटन कराया गया है वह जिला कलेक्टर की परमिशन के वगैर कराया है जो स्वतः निरस्त योग्य है। तथा मौके पर कभी भी आवंटी का कब्जा नहीं रहा है तथा उसके द्वारा जो विक्रय पत्र तहरीर किया गया है उसका कब्जे के वगैर कोई महत्व नहीं है। रेस्पो० का यह कथन कि विवादित भूमि पर उनके काशत के खातेदारी में दर्ज है मात्र एक राजस्व प्रविष्टि है जिसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि मौके पर भौतिक रूप से रेस्पो० का कब्जा नहीं है। साक्ष्य में जो पाँच रुपये का स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है वह ना तो ज्यून डॉक्यूमेंट है ना ही दाखिले शहादत माना जा सकता है। भूमि पर आवंटन से पूर्व अपीलांट के पिता का कब्जा चला आ रहा है तथा उसके पश्चात उनका कब्जा चला आ रहा है। भूमि पर रिहायशी लकजनी हुए हैं और 50 वर्षों से भी अधिक समय से रिहायश में इस्तेमाल होती चली आ रही है। भूमि आबादी की परिभाषा में आती है क्योंकि रिहायशी मकान के रूप में उस भूमि का लगातार इस्तेमाल होना इस बात का सबूत है कि यहाँ भूमि अपीलांट की मिलिकयत में निहित हो चुकी है और उससे संबंधित केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही विवाद को अंतिम रूप से निपटाया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय को इस वाद को सुनवाई का अधिकारी नहीं है। इसलिए आदेश मातहत निरस्त योग्य है। अपीलांट का इस भूमि पर लम्बे समय से लगातार कब्जा होने के कारण बैसी भी By way of adverse possession स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आदेश व डिग्री निरस्त योग्य है। रेस्पो० का वादग्रस्त भूमि से दूर तक कोई वास्ता संबंध नहीं है। केवल मात्र पेपर पजेशन के आधार पर वाद पत्र निर्णित किया गया है। कानून का निश्चित रूप से यह सिद्धान्त है कि स्थाई निषेधाज्ञा उसी स्थिति में जारी हो सकती है जबकि विवादित आराजीयात पर भौतिक रूप से कब्जा साबित हो जावे। महज एक प्रजम्पशन के आधार पर फर्जी स्टाम्प की तहरीर जिसका कानूनी एतवार से कोई महत्व नहीं है उसको आधार बनाकर वाद का कारण मानने में भारी भूल की है। क्योंकि विवादित भूमि पर उसके परिजनो के समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिए अपीलांटान By way of adverse possession उसके स्वामित्व हो चुके हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया गया है इसलिए आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व डिग्री दिनांक 14.5.14 निरस्त फरमाया जावे।

अपील अग्रिम

22/5/14
अपील अग्रिम
स्वायं मन्व

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम पीपल्या की आराजी ख0न0 1110,1111,1115,1116,1117 कुल किता 5 कुल रकबा 1.88 है0 जो रेस्पो0 की खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी है। पूर्व में इस भूमि का ख0न0 653 था। अपीलान्तान 1 व 2 ने रेस्पो0 की आराजी ख0न0 1116 रकबा 0.05 है0 पर बाडा व मकान बनाकर एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने ख0न0 1117 रकबा 0.01 है0 पर बाडा बनाकर तथा प्रतिवादी न0 4 व 5 ने ख0न0 1117 में 0.01 है0 पर बाडा बनाकर जबरन रेस्पो0 की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कांटों की बाड लगाकर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा सन 1995 में उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर बाडा व मकान बनाने का प्रयास करने पर रेस्पो0 के पिता द्वारा तहसीलदार को शिकायत करने पर तहसीलदार प्रतिवादीगण को बेदखल कर अतिक्रमण हटवा दिया था तथा जमीन जमा करवा दी थी। तत्समय प्रतिवादीगण ने रेस्पो0 के हक में पाँच रुपये का स्टाम्प पेपर पर यह लिख कर दे दिया कि हमने बाडा बंगै0 हटा लिया है मकान को फोडकर मलबा हटा लिया है। अब भविष्य में रेस्पो0 की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। दिनांक 10.9.05 को प्रतिवादीगण ने फिर रेस्पो0 को परेशान करना शुरू कर दिया व उक्त भूमि पर दुबारा अतिक्रमण कर बाडा व खाम मकान निर्माण कर लिया जिसकी बजह से रेस्पो0 की काशत की भूमि को जबरन अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिया जिससे रेस्पो0 के खेत का रास्ता बंद हो जाने की आशंका हो गई। इस कारण ही रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्त केवल मात्र एडवर्स पजेसन के आधार पर कानूनी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। जिन्हे उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एडवर्स पजेसन के आधार पर किसी प्रकार के हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे वादी/रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सभी पैराओं को स्वीकार किया गया है तथा उक्त आराजीयात को वादीगण/रेस्पो0 की खातेदारी में माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का पूर्ण विवेचन कर तथा दोनो पक्षों के बयान कलमवद्ध किये जाकर उभयपक्ष की बहस दावे में सुनकर तथा प्रत्येक दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात ही अपीलान्धीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है। इस प्रकार अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड नकल खतौनी बन्दोवस्त सम्बत 2058 के अनुसार अपीलान्त नरपत सिंह, उम्मेद सिंह, गणपत सिंह पिसरान नन्दलाल जाति राजपूत सा0 देह खातेदार अंकित है। जिससे सिद्ध है कि विवादित आराजीयात वादी/रेस्पो0 की खातेदारी की आराजीयात है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.10.03 के विवादित भूमि रेस्पो0/वादी की खातेदारी भूमि होने का अंकन है तथा उस पर अपीलान्त/प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का अंकन है। दस्तावेजात से भूमि वादीगण/रेस्पो0

की खातेदारी सिद्ध है तथा प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से पॉच 0.05 है० भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसका अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का कथन रहा कि विवादित भूमि पर अपीलान्टान का आवंटन से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है यदि ऐसा है तो अपीलान्टान द्वारा वादी/रेस्पों को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए थी। जो अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है तथा बंदी सिंह का आवंटन बहाल रहा उसके पश्चात बंदी सिंह को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तत्पश्चात वादीगण को विवादित भूमि क़य कर दी गई। इस प्रकार विवादित भूमि वादी/रेस्पों की राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी की आराजीयात है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलान्धीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलान्ट अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु०न० 366/11 निर्णय दिनांक 14.5.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Am 10.2.20
(बी०एल०रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

